view to improve the capacity to achieve targets and remove past short-comings.

(ii) Changing procedures and priorities so as to ensure timely and adequate availability of all required inputs including funds.

(iii) Installing effective multi-tiered monitoring systems so as to watch performance and supply timely correctives wherever necessary.

मध्य प्रदेश में गाड़ियों का नियमित समय पर चलना ।

6791. **श्री गंगाचरण दीक्षित** : क्या **रेल** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मध्य प्रदेश में विशेषकर अमृतसर-दादर और दादर-अमृतसर एक्स-प्रेस रेलगाड़ी नियमित समय पर नहीं चल रही हैं; और

(ख) यदि हां, तो गाड़ियों को नियमित समय पर चलाने के लिए सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की जा रही है ?

रेल मंत्रालय में उपमंत्री (श्री मुहम्मद शफ़ी कुरेशी) : (क) विभिन्न कर्मचारियों और जन आन्दोलनों, बंद आदि तथा कुछ मामलों में बहुत अधिक खतरे की जंजीरों के खींच जाने के कारण सामान्यतः अस्थिर स्थितियों के कारण पिछले कुछ महीनों के दौरान सभी रेलों पर गाड़ियों के समय-पालन पर, जिसमें 57/58 दादर-अमृतसर एक्सप्रेस भी शामिल है, दुष्प्रभाव पड़ा है ।

(ख) खतरे की जंजीर खींचने की घटनाओं की रोकथाम और कानून तथा व्यवस्था में सुधार के लिए राज्य सरकार की सहायता प्राप्त की जाती है इसके अलावा परिहार्य कारणों की जांच की जाती है तथा उन पर कार्रवाई भी की जाती है ताकि गाड़ियों के चालन में सुधार किया जा सके ।

मध्य देश में छत्तीसगढ़ क्षेत्र में रेलवे लाइन

6792. **श्री गंगाचरण दीक्षित** : क्या **रेल** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मध्य प्रदेश के किन-किन क्षेत्रों में पांचवीं योजना के अन्तर्गत नई रेलवे लाइनें बनवाने की योजना है ;

(ख) क्या सरकार का विचार छत्तीसगढ़ क्षेत्र (मध्य प्रदेश) में नई रेलवे लाइन बनवाने का है; और

(ग) यदि हां, तो कब तक और यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

रेल मंत्रालय में उपमंत्री (श्री मुहम्मद शफ़ी कुरेशी) : (क) पांचवीं पंचवर्षीय योजना में शुरू किये जाने वाले नई लाइनों के निर्माण से सम्बन्धित प्रस्तावों को अभी अन्तिम रूप नहीं दिया गया है ।

(ख) और (ग). दल्ली राजहरा से जगदलपुर / दांतेवाड़ा तक एक रेल लाइन के निर्माण के लिए सर्वेक्षण का काम शुरू किया गया है । सर्वेक्षण कार्य के पूरा हो जाने के बाद ही इस लाइन के निर्माण के सम्बन्ध में कोई विनिश्चय किया जायेगा ।

वर्ष 1973–74 के दौरान मध्य प्रदेश में ग्रामीण विद्युतीकरण

6793. **श्री गंगा चरन दीक्षित**: क्या सिंचाई और विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि वर्ष 1973–74 में मध्य प्रदेश के प्रत्येक जिले में कौन-कौन से गांवों में बिजली लगाई गई ?

सिंचाई और विद्युत् मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सिद्धेश्वर प्रसाद) : मध्य प्रदेश में 1973–74 के दौरान 28–2–1974 तक 526 ग्रामों का विद्युतीकरण किया गया था । प्रत्येक जिले में विद्युतीकृत

ग्रामों के नाम 1-4-1973 से 30-9-73 तक की अवधि के लिए ही उपलब्ध हैं। ये सभा पटल पर रखे गये विवरण में दिये गये हैं। [ग्रन्थालय में रख दिया। देखिए संख्या L.T. 6712/74]

मध्य प्रदेश सरकार को खाद्यान्नों की सप्लाई न करना

6794. श्री गंगाचरण दीक्षित : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उत्तरी क्षेत्र से वैगनों के उपलब्ध न होने के कारण मध्य प्रदेश सरकार को खाद्यान्नों की सप्लाई नियमित रूप से नहीं हो रही है ;

(ख) क्या मध्य प्रदेश सरकार ने इस मामले की जांच करने के लिए केन्द्रीय सरकार से अनुरोध किया है ;

(ग) यदि हां, तो उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है; और

(घ) खाद्यान्नों की सप्लाई करने के लिए गत चार महीनों में राज्य को कितने वैगन आवंटित किये गये हैं ?

रेल मंत्रालय में उपमंत्री (श्री मुहम्मद शफ़ी कुरेशी) : (क) जी नहीं।

(ख) जी नहीं।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

(घ) दिसम्बर 73 से मार्च 1974 तक की अवधि में उत्तरी क्षेत्र से मध्य प्रदेश के लिए खाद्यान्न ढोने का कोई कार्यक्रम नहीं था। लेकिन उस अवधि में सरकारी लेखों में 28 फुटकर मांगें आयी जिन्हें पूर्णतः पूरा किया था।

Execution of Schemes by R.E.C. in Kerala in 1974-75

6795. SHRI VAYALAR RAVI: Will the Minister of IRRIGATION AND POWER be pleased to state:

(a) the important schemes to be executed in the State of Kerala with the assistance of the Rural Electrification Corporation during the year 1974-75, and a brief outline of these schemes and the total amount sanctioned for the execution of these schemes;

The DEPUTY MINISTER IN THE MINISTRY OF IRRIGATION AND POWER (SHRI SIDDESHWAR PRASAD): (a) and (b). The programme of rural electrification is formulated by the State Governments and implemented through their State Electricity Boards, Additive loan finance is provided by the Rural Electrification Corporation Ltd., for implementation of viable schemes of the State Electricity Boards Upto 31-3-1974, the Corporation has sanctioned 16 schemes of the Kerala State Electricity Board involving a loan assistance of Rs. 712,571 lakhs Details of the schemes are given in the statement laid on the Table of the House. [*Placed in Library. See* No. LT-6713/74]. these schemes are scheduled for completion in a period of 3-5 years and will continue to be executed during the year 1974-75.

No details are available for the schemes which may be sponsored by the Kerala State Electricity Board during 1974-75. The assistance would depend upon the number of schemes sponsored by the Kerala State Electricity Board and approved by the Corporation in accordance with the laid down norms and guidelines.

Amount recovered from Ticketless Travellers during 1973-74

6796. SHRI SUKHDEO PRASAD VERMA: Will the Minister of RAILWAYS be pleased to state: